सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-31 अंक-13 7 जुलाई, 2016 मुख्य संपादक कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती कुल पृष्ठ 8 मूल्य : 2 रुपये

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लूट की बेलगाम छूट दे देगा 100% एफडीआई का कदम

– एसयूसीआई(सी)

एफडीआई के नये फैसले पर एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 21 जून को निम्नलिखित बयान जारी किया :

केन्द्र की बीजेपी सरकार ने नागरिक उड्डयन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की इजाजत देने और रक्षा व फार्मास्युटिकल यानी दवा उद्योग और सिंगल ब्राण्ड रिटेल में नियमों में छूट देने के अपने निर्णय का ऐलान किया है। सरकार ने दावा किया है कि यह निर्णय ''भारत को एफडीआई के लिए दुनिया में सबसे खुली अर्थव्यवस्था बना देगा'' और अब ज्यादातर क्षेत्र स्वत: अनुमति के रूट के तहत हो जायेंगे।'' ये कदम देश के प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों और श्रमशक्ति को लूटने तथा आम आदमी के खून के आखरी कतरे तक को चूसने की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बेलगाम छूट दे देगा। रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बाबत सुरक्षा सम्बन्धी चिंताओं के अलावा, अप्रतिबंधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बुरे असर ये होंगे : देश के संसाधनों का देश से बाहर दोहन होना, गरीब किसानों, मजदूरों और व्यापारियों की रोजी-रोटी छिन जाना, मजदूरों के बड़े कष्टों से हासिल किये गये अधिकारों में कटौती और कार्यस्थलों पर काम करने की अत्याचारपूर्ण कठोर शर्तें। इन सबकी अवहेलना करते हुए शासक पूंजीपति वर्ग अमेरिका-नीत साम्राज्यवादी ताकतों की कृपादृष्टि पाने और दोस्ती जीतने के इरादे से विदेशी पूंजी को बेलगाम लाइसेन्स दे रहा है, वह उनकी मदद से अपनी सैन्य क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा है, दूसरे देशों में भारतीय एकाधिकारी पूंजी को लगाने की उद्देश्य प्राप्ति के लिए तरीका अपना रहा है और अपने आपको क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए साम्राज्यवादियों का समर्थन पाना चाहता है।

हम लोगों से अपील करते हैं कि शासक वर्ग के इस बुरे मन्सूबे से सचेत रहें और लोगों से पुरजोर आग्रह करते हैं कि विदेशी पूंजी के साथ मिलकर मेहनतकश लोगों का निर्मम शोषण तेज करने की भारतीय पूंजीपति वर्ग की साजिश को नाकाम करने के लिए जोरदार जनवादी जनआन्दोलन गठित करें और सरकार को अपना फैसला रद्द करने के लिए मजबूर कर दें।

थोथा चना बाजे घना

मोदी सरकार की सफलता की विज्ञापनी चमक

मोदी सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर सफलता के विभिन्न विज्ञापनों से संवाद माध्यम भरे पड़े हैं। रेडियो, टी.वी. पर व्यापक प्रचार और अखबारों में पूरे पन्ने के विज्ञापनों पर नजर जरूर पड़ेगी। इनमें सरकार के नए नारे –'ट्रांस्फार्मिंग इण्डिया' को पेश किया गया है जिसका मतलब है भारत बदल रहा है। मोदी सरकार के शासन की बदौलत भारत की छवि किस तरह बदल रही है, प्रचार में इसी को दिखाया जा रहा है।

कितनी आश्चर्य की बात है सफलता यदि इतनी ही छप्पर फाड़ हो, वह यदि जीवन पर असर डाल रही हो तो इतना ढोल पीटने की क्या जरूरत है? कहावत है थोथा चना बाजे घना।

मोदी सरकार के दो वर्ष पूरे होने का तोहफा है–टैक्सों में और भी बढ़ोतरी। सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी, छंटनी के बोझ तले दबे जन साधारण के कंधों पर सभी सेवाओं पर लगने वाले कृषि कल्याण सैस के नाम पर 0.5% टैक्स बढ़ोतरी का बोझ लाद दिया। इसके अलावा स्वच्छता कर लगा दिया है। बार-बार पैट्रोल-डीजल-रसोई गैस के दाम बढ़ाये गए हैं। रेल किराया, फोन का बिल, माल ढुलाई, स्वास्थ्य सेवाओं सहित तरह-तरह के खर्चे बढ़ गए हैं। इसके चलते सेवा करों की कुल मिला कर मात्रा 15% हो गयी है। त्रस्त जन साधारण पर इसके बढ़ते हुए बोझ को लादने के अमानवीय काम को लोगों की नजर से ओझल करने के लिए 'कल्याण' नाम देकर कहा जा रहा है 'कृषि कल्याण सैस'।

विगत दो वर्षों में मोदीजी किसानों के प्रति क्या नजरिया लेकर चले हैं जिससे समझा जा सके कि यह सरकार किसानों के कल्याण के लिए सचमुच में ही कुछ करेगी? कुछ दिनों पहले ही 13 राज्यों में सूखा घोषित हुआ है। भारी संख्या में कृषि पर निर्भर लोग सिंचाई के पानी के लिए हाहाकार कर रहे हैं, पीने के पानी के लिए हाहाकार करते हुए हजारों-हजार लोगों को प्रकृति के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है। लेकिन 'किसान-हितैषी' सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को दुरूस्त करने के काम को कोई महत्व नहीं दिया। आपदा पीड़ित किसानों के कर्जे माफ नहीं किए। फिर भी सूखाग्रस्त महाराष्ट्र में मोदी सरकार की मेहरबानी से क्रिकेट पिच के लिए हजारों-हजार गैलन पानी का कोई अभाव नहीं हुआ। पानी माफियाओं के लिए सरकार पानी की आपूर्ति करती रही। मुनाफाखोर चीनी मिल मालिकों पर सरकार पूरी मेहरबान है। क्योंकि मंत्री अथवा सत्ताधारी नेता ही ज्यादातर चीनी मिलों के मालिक हैं। वे गन्ना उत्पादक किसानों का लाखों रुपया मारे बैठे हैं। बड़े-बड़े पूंजीपति बैंकों का हजारों करोड़ रुपया मारे बैठे हैं। उन्होंने बैंकों से लिए कर्ज का ब्याज तक नहीं चुकाया है। सरकार ने खुद उनको सम्पत्ति कर और अन्य करों में भारी छूट दी है। सरकार की कृषि नीति के चलते कर्जवान होकर अथवा लाभकारी दामों पर फसल की बिक्री न कर पाने की वजह से सिर्फ पिछले तीन सालों में 3000 किसान मारे गए हैं। सिर्फ 2015 में ही 2000 किसानों

(शेष पृष्ठ 2 पर)

एफडीआई के विरोध में वाम दलों ने दिया धरना

नई दिल्ली : रक्षा, खुदरा व्यापार, डीटीएच केबल और घरेलू विमानन जैसे क्षेत्रों में 100 फीसद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी देने के विरोध में वाम दलों – माकपा, भाकपा, एसयूसीआई(सी) और सीजीपीआई ने 27 जून को जंतरमंतर पर धरना दिया और केन्द्र की मोदी सरकार पर भारतीयों की बजाय विकसित देशों के हितों की रक्षा करने के लिए गलत फैसले लेने का आरोप लगाया।

इससे सुरक्षा संबंधी चिंता बढ़ गई है। ओटोमेटिक रूट के जरिये 74 फीसद एफडीआई से भारतीय दवा कंपनियों पर कब्जा जमा पाना आसान हो जाएगा। निजी सुरक्षा एजेंसियों में एफडीआई की सीमा को 49 फीसद से बढ़ा कर 74 फीसद कर दी गई है, सिंगल ब्राण्ड रीटेल में लोकल सोर्सिंग की शर्त को भी खत्म कर दिया गया है।

माकपा की पोलिट ब्यूरो सदस्या वृन्दा करात, भाकपा की सचिव अमरजीत कौर, माकपा के वेकएम तिवारी, एसयूसीआई (सी) के रमेश शर्मा व प्रताप सामल और सीजीपीआई के बिरजू नायक ने धरने को सम्बोधित किया। धरने की अध्यक्षता भाकपा के दिनेश वार्ष्णेय ने की।

थोथा चना बाजे घना...

(पृष्ठ 1 का शेष)

ने आत्महत्या की है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े बता रहे हैं कि देश में हर रोज 46 किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस हकीकत से सरकार अनजान नहीं है। सरकार के कृषि हितैषी होने से इस सब पर रोक लगाने के लिए प्रयास करना क्या जरूरी नहीं था?

देश के 60% लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, वहां प्रशासनिक अवहेलना और सरकारी उदासीनता के चलते, जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान मात्र 15% है। यानी श्रम शक्ति और विज्ञान का उचित उपयोग होता तो कृषि से जीडीपी में कई गुना ज्यादा योगदान हो सकता था। देश में कृषि मंत्रालय है, कृषि मंत्री हैं, कृषि विशारद हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं लेकिन कृषि व्यवस्था पर गौर करने वाला कोई नहीं है। आधुनिक पद्धति से किसानों को खेती का काम सिखाने के लिए कोई भी संस्थान नहीं है। कृषि संबंधित संस्थानों के साथ किसानों को जोड़ा ही नहीं गया। देशी-विदेशी पूंजीपति मालिकों के स्वार्थ में भूमि अधिग्रहण बिल पास कराना चाहती है सरकार। श्रम कानूनों में संशोधनों से मोदी सरकार का श्रमिक-विरोधी चरित्र पूरी तरह से उजागर हो गया है। इसी तरह हर एक सवाल पर समझ आ रहा है कि मोदी सरकार कतई किसान हितैषी नहीं है। इसमें जनता के प्रति लेशमात्र भी हमदर्दी नहीं है। किसान हितैषी होने का दिखावा कर कृषि कल्याण सैस लगाकर सरकारी खजाने को और भी भरने का असल मकसद क्या पूंजीपतियों को और भी अनुदान देना नहीं है?

मोदी सरकार के वित्तमंत्री अरूण जेटली ने जो बजट पेश किया है उसी से समझ में आ गया था कि यह कितनी किसान हितैषी है । वर्ष 2015 के कृषि बजट में आवंटन से 3272 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई है। गत वर्ष इस मद में 31,322 करोड़ रुपया की धनराशि आबंटित की गई थीं जिसे इस साल घटाकर 28,050 करोड़ रुपया कर दिया गया है। खाद्य उत्पादन में आबंटित धनराशि 47,681 करोड़ रुपये से घटाकर 39,868 करोड़ रुपया कर दी गई है। पशु पालन में आबंटित धनराशि 599 करोड़ रुपये से घटाकर 330 करोड़ रुपया कर दी गई है। बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजना के लिए आबंटित धनराशि 1,121 करोड़ रुपये से घटाकर 572 करोड़ रुपया कर दी गई है। छोटी सिंचाई परियोजना के लिए आबंटित धनराशि 468 करोड़ रुपये से घटाकर 306 करोड़ रुपया कर दी गई है। यह है इसके किसान-हितैषी होने का नमूना।

2016-17 के बजट में सिंचाई व्यवस्था का विकास, सोशल हैल्थ कार्ड चालू करने, जैव प्रौद्योगिक से खेती की विभिन्न सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज चालू करने की घोषणाएं की गई हैं। 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना', 'परम्परागत कृषि विकास योजना' इत्यादि विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा की गई है। लेकिन इन सब परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित नहीं की गई है। फिर भी सरकार ने उर्वरक कम्पनियों का हित साधने के लिए 'मॉडल रिटेल आऊटलेट' खोलने की व्यवस्था की है। खाद्यान्न व्यापारियों के कारोबार की खातिर मेगा फूड पार्कों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की गई है। हरिद्वार में इसी तरह के एक मेगा फूड पार्क के मालिक मोदी के गुणग्राही हैं 'बाबा रामदेव'। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में मल्टीब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर सरकार जोर दे रही है। कंगाल किसान फसल के वाजिब दाम न मिलने पर आत्महत्या का रास्ता अपनाने पर मजबूर हो रहे हैं इसके बावजूद सरकार कृषि क्षेत्र को देशी-विदेशी पूंजीपतियों के अबाध मुनाफे के क्षेत्र में परिणत कर रही है।

बजट में ही 'कृषि कल्याण सैस' की घोषणा की गई थी। 1 जून से इस सैस में जुड़ जाने से सेवा कर का कुल परिमाण हो गया है 15%। ट्रेन की टिकट, माल ढुलाई, फोन का बिल, आर्थिक लेनदेन, केबल टी.वी, पार्सल भेजने इत्यादि जैसी सेवाएं इसमें शामिल हैं जो हर एक आम आदमी की रोजमर्रे की जरूरतों के साथ जुड़ी हुई हैं। इसके भी ऊपर है पैट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों में भारी कमी होने के बावजूद पैट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किए गए हैं। इसके विपरीत मोदी सरकार के दो वर्ष के शासनकाल में पैट्रोल के दाम 16 बार और डीजल के दाम 19 बार बढ़ाए गए हैं। इसके प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव से रोजमर्रा की उपयोगी चीजों के दाम भयंकर गति से बढ़ रहे हैं। रसोई गैस गृहस्थी का लाजिमी हिस्सा है, लेकिन इसके दाम निरंतर ही बढ़ते जा रहे हैं। बिजली के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। जन हितैषी सरकार यदि हो तो उत्पादन शुल्क घटाकर पैट्रोल और डीजल के निरंतर बढ़ रहे दामों से आम आदमी की रक्षा कर सकती थी। ये तो किया ही नहीं उल्टे पैट्रोल-डीजल पर शुल्क लगाकर पिछले एक साल में ही 20 हजार करोड़ रुपये की आमदनी कर ली है। यहां तक कि राजस्व की आमदनी बढ़ाने के लिए धारावाहिक रूप से पैट्रोल-डीजल पर उत्पादन शुल्क बढ़ाया गया है। इन दो सालों में उत्पादन शुल्क सरकार ने दोगुना से ज्यादा कर दिया है। मोदी सरकार के हर एक कदम से ही इसका जनविरोधी चरित्र नग्न रूप से उजागर हुआ है। लेकिन वे जन हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं।

इससे पहले भी मोदीजी के 'अच्छे दिनों' का नमूना लोगों ने देखा है। 'मेक इन इण्डिया', 'सबका साथ सबका विकास' के नारे और भ्रष्टाचार रोकने के लिए 'न खाऊंगा न खाने दूंगा' इत्यादि नारों की परिणति पर सबने गौर किया है। मोदीजी के बहुत से आश्वासनों की अकाल मृत्यु की बात किसी से छिपी नहीं है। भ्रष्टाचार रोकने, कालाधन वापस लाने आदि बहुत से वादे करके बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी। अब भ्रष्टाचार की दलदल में पूरी तरह से डूबी हुई बीजेपी का भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा गले की हड्डी बन गया है। हाल ही में, महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के राज्य मंत्री एकनाथ खड़से जमीन घोटाले सहित विभिन्न घोटालों में अभियुक्त होकर त्यागपत्र देने के लिए मजबूर हुए हैं। बिहार के राज्यसभा में बीजेपी के निर्वाचित सदस्य एक कोयला माफिया हैं। 'ट्रांस्फोर्मिंग इण्डिया' अथवा 'कृषि कल्याण सैस' के नाम पर किसानों की उन्नति का नारा भी इन सब की तरह ही एक थोथा नारा है। असल में मोदीजी किसान हित की कितनी ही बात क्यों न कहें लेकिन सब कुछ कर रहे हैं पूंजीपतियों की स्वार्थ की रक्षा हेतु। छोटे किसानों के लिए नहीं बल्कि कृषि व्यापार से जुड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों अथवा कृषि क्षेत्र में घुसने के इच्छुक देशी-विदेशी पूंजीपतियों के स्वार्थ में पहले की कांग्रेस सरकार की तर्ज पर ही यह सरकार काम करती जा रही है। जिन पूंजीपतियों ने इसको धन मुहैया करा कर सब तरह की मदद देकर सत्ता में बैठाया है उनका स्वार्थ साधे बिना तो उनका काम नहीं चलेगा। लेकिन उनकी स्वार्थरक्षा की बात तो खुल्लमखुल्ला नहीं कही जा सकती है। इसीलिए है कृषि हितैषी होने का छलावा।

किसान-खेतमजदूरों की ज्वलंत मांगों पर सौंपा ज्ञापन

हरियाणा में किसानों-खेत मजदूरों की ज्वलंत मांगों पर ऑल इण्डिया कृषक खेत मजदूर संगठन (ऑल इण्डिया के के एम एस) की विभिन्न जिला कमेटियों की ओर से 21 जून को डी.सी. दफ्तरों पर धरने- प्रदर्शन किये गये और जिला उपायुक्त की मार्फत मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपे गये।

ज्ञापन में मांग की गई : गरीब किसान-खेत मजदूरों के कर्जे समाप्त करो। फसलों के लाभकारी दाम दो. फसल खराबे का मुआवजा 50 हजार प्रति एकड़ तय करो, जिसे सरकार अपने खजाने से देना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आड़ में प्राइवेट कम्पनियों की घुसपैठ पर सरकार रोक लगाये। पेट्रोल-डीजल के दाम बार-बार बढ़ाना बन्द करो, खेती में डीजल के दाम आधे करो। गांव शामलात व पंचायती भूमि में ग्रामसभा के मालिकाने हक में सरकारी दखलअन्दाजी पर रोक लगाओ। महंगाई पर रोक लगाओ, नये राशन कार्ड बनाकर सभी परिवारों को सस्ता राशन दो। गरीब किसानों, भूमिहीन गरीबों, खेत मजदूरों, चिनाई के मजदूर मिस्त्रियों को बी.पी.एल. सूची में शामिल करो। मनरेगा में मजूदरी 500 रु. लागू करो। सरकारी स्कूलों में पहली क्लास से पास-फेल परीक्षा प्रणाली लागू करो। खाद-बीज के सरकारी बिक्री केन्द्र ब्लॉक स्तर पर खोले जायें और बिजाई से पहले बीज उपलब्ध कराये जायें। खनन कार्य से फसल पर पड़ने वाले कुप्रभाव को रोका जाये। बुढ़ापा पेन्शन 2000 रुपये मासिक की जाये। इस पर लगाई गई तमाम नाजायज शर्तें हटाई जायें।

किसान नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की तरह भाजपा सरकार भी किसान-विरोधी नीतियां लागू कर किसान मजदूरों का कचूमर निकाल रही है। गद्दी में आते ही मोदी सरकार ने गेहूं व धान पर बोनस देने पर रोक लगा दी। कृषि भूमि प्राइवेट कम्पनियों को देने के लिए रातों-रात तीन बार अध्यादेश जारी किया जो किसानों व खेत मजदूरों के आन्दोलन के दबाव में वापिस लेना पड़ा। कृषि उपज पर 50 प्रतिशत लाभकारी दाम देने के अपने वायदे से मुकर गई। यूरिया के लिए किसान मारे-मारे फिरे। डीजल के दाम बार-बार बढ़ाये जा रहे हैं। बिजली महंगी कर दी व इन्हें प्राइवेट कम्पनियों के हवाले कर दिया। कृषि सब्सिडी में कटौती की जा रही है। काला धन लाने के जुमले की तरह 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने की बातें किसानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए बनाई जा रही हैं। कर्ज के बोझ तले दबे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। भाजपा सरकार तो समर्थन मूल्य पर फसलों की सरकारी खरीद को ही बन्द करना चाहती है और ई-मण्डी की आड़ में प्राइवेट कम्पनियों के चंगुल में फंसाना चाहती हैं। मोदी सरकार की प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना एक धोखा और निरा ढोंग है। इस योजना के तहत सरकारी खजाने से फसलों का मुआवजा देने की मौजूदा नीति समाप्त की जा रही है। केवल उन्हीं किसानों को मुआवजा दिया जायेगा जो प्राइवेट कंपनियों को अपने जेब से पैसा देकर फसल बीमा करायेंगे। कड़ी शर्तों पर मुआवजा की रकम भी बहुत कम होगी। कर्ज में दबे गरीब किसान खेत मजदूरों को कोई राहत नहीं दी जा रही। मनरेगा में मजदूरी गांव में चालू दिहाड़ी से भी कम है। महंगाई व बेरोजगारी ने सभी का जीना मुश्किल कर दिया है। उन्होंने किसान-खेतमजदूरों का आह्वान किया कि अपने हक-हकूक पाने के लिए एकजुट हो, संगठन को मजबूत बनायें और आन्दोलन तेज करें।

इस अवसर पर भिवानी में संगठन के राज्य उपाध्यक्ष कॉ. विजय कुमार, जिला सचिव रोहताश, जिला अध्यक्ष कॉ. जिले सिंह, सुखबीर, उदयवीर, फूल सिंह, राजकुमार, वजीरचंद आदि शामिल थे। कैथल में जिला अध्यक्ष कॉ. बाबू राम, रामसरूप, सुभाष, कृष्ण, दर्शन, चमेल सिंह, धर्मपाल, महावीर, महेन्द्र आदि शामिल थे। झज्जर में धरने की अध्यक्षता संगठन के राज्य सचिव कॉ. जयकरण माडौठी ने की जबकि धरने में जिलाध्यक्ष कॉ. करतार सिंह अच्छेज, जिला सचिव ईश्वर सिंह बराही भी मौजूद थे। कुरूक्षेत्र में लघु सचिवालय पर धरने में एसयूसीआई(सी) के जिला सचिव कॉ. रोशन लाल और एआईकेकेएमएस के जिला सचिव कॉ. राजकुमार के अलावा गुरदयाल सिंह, रघुबीर सिंह, रामफल, श्यामलाल, गुलाब सिंह आदि उपस्थित थे।

मजदूर आन्दोलन में क्रान्तिकारी दृष्टिकोण क्या हो

– शिवदास घोष

(गतांक से आगे)

बुर्जुआ कुसंस्कृति के शिकार या दुर्दशाग्रस्त मजदूर की संस्कृति ही सर्वहारा संस्कृति नहीं

केवल राजनैतिक रूप से या केवल नारों से सर्वहारा दुनिया को नहीं बदल सकते। बुर्जुआ संस्कृति की कूपमंडूकता से मुक्त होकर अपने आचरण से, नीति-नैतिकता से, रुचि-संस्कृति से, आचार-विचार से, अपने बीच क्रान्तिकारी नेतृत्व को जन्म देने में सफल हुये सर्वहारा ही दुनिया को बदल सकते हैं। जब तक मजदूर बुर्जुआ माहौल से प्राप्त बुर्जुआ व्यक्तिवाद, विचारधारा व कुसंस्कृति के प्रभाव से मुक्त नहीं होता तब तक महज आर्थिक दुर्गति के बढ़ने से वे क्रान्ति नहीं कर सकते। बुर्जुआ संस्कृति का जो विकृत रूप मजदूरों में पाया जाता है, क्योंकि मजदूरों में पाया जाता है इसीलिए वह "सर्वहारा संस्कृति" नहीं हो जाती। एक समय मानव कल्याण के विचारों से प्रभावित कुछ लोगों का सोचना था कि मजदूरों के बीच जो कुछ भी है वही क्रान्तिकारी है। इसलिए मार्क्स से लेनिन तक सभी ने ऐसे लोगों के कान ऐंठते हुये सिखाया था कि सर्वहारा संस्कृति का मतलब यह नहीं होता कि 'संस्कृति खुद ही सर्वहारा' (Culture itself proletariate) हो। उन्होंने कहा कि बुर्जुआ क्रान्ति के आदर्श पर मानवतावादी मूल्यबोध एवं उदारवादी दृष्टिकोण का ढाँचा विकसित हुआ था। मजदूर क्रान्ति के युग में क्रान्ति के आदर्श के आधार पर सर्वहारा संस्कृति हासिल करने का मतलब अज्ञानी, अशिक्षित व बुर्जुआ संस्कृति के कुप्रभावों से ग्रसित सर्वहारा की बातों, आदतों को अपनाना नहीं है, जो मजदूर आज बुर्जुआ कु-संस्कृति व दुर्दशाग्रस्त जीवन से जकड़े हुये हैं, किस्मत की दुहाई देकर, जीवन की इस बदहाली को ही सत्य मानकर, अपरिवर्तनीय नियम मानकर चल रहे हैं, आर्थिक अवसरवाद के गोरख धंधे में फँसे हुये हैं, उन्हें आर्थिक दलदल से मुक्त कर संजीदगी के साथ खड़ा कर, नये आदर्शों से लैस कर कम्युनिस्ट बनाने के लिये सर्वहारा संस्कृति है। परन्तु मैं भारत में उल्टी ही चीज देखता हूँ। देखता हूँ यहाँ मजदूरों के बीच जाने एवं उनके साथ घुलने-मिलने के लिये तथाकथित कम्युनिस्टों को भांग खाना व गाँजा पीना पड़ता है। एक समय लेबर पार्टी में कितने ही कार्यकर्ता घर-बार छोड़कर सर्वस्व त्यागकर क्रान्ति करने आये थे। एक बड़ी पार्टी जिसने खुद मजदूरों के बीच से इतने अधिक कार्यकर्ताओं को पाया था, उतने कार्यकर्ता हमलोगों ने किसी पार्टी में नहीं देखे। आज हम लोग उसका कैसा दयनीय परिणाम देख रहे हैं। सर्वहारा संस्कृति की शिक्षा देते हुये उसने सब कार्यकर्ताओं को अत्यधिक दुर्दशाग्रस्त सर्वहारा में बदल दिया। एक भी कार्यकर्ता को वे क्रान्तिकारी नहीं बना पाये। कितने ही कार्यकर्ताओं को उन्होंने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वे लोग मजदूरों को जागृत करने में खुद ही बुर्जुआ कुसंस्कृति और नैतिक पतन के शिकार मजदूर के रूप में परिणत हो गये। बस इसी दलदल में फँस कर उनकी तमाम सम्भावनाएँ नष्ट हो गई। इसलिये मार्क्सवादी आन्दोलन या मजदूर आन्दोलन के विजयी होने की यह प्रधान शर्त है-"यदि मजदूर पहले अपने को बदल नहीं सका तो वह दुनिया को भी नहीं बदल सकेगा"। इसी वजह से सर्वहारा संस्कृति की नींव पर, सही राजनैतिक लाइन के आधार पर, सही क्रान्तिकारी पार्टी के नेतृत्व कायम करने का प्रश्न, क्रान्ति के प्रश्न के साथ ओत-प्रोत रूप से जुड़ा हुआ है। मजदूरों के हाथों में जो एकमात्र अजेय हथियार है उसी मार्क्सवाद-लेनिनवाद के विज्ञान के आधार पर मजदूर वर्ग को वर्ग-संघर्ष के अंदरूनी नियम व स्वरूप के बारे में एवं देश की आर्थिक-राजनैतिक-सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण ठीक-ठीक समझना होगा। अभाव, भूख, अत्याचार, जुल्म के खिलाफ जो रोज-रोज लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं उन्हें आखिरकार कहाँ कौन-सी मंजिल पर ले जाना होगा–इस बात को समझना होगा। कौन शोषण कर रहा है, किसके खिलाफ लड़ाई है, इन बातों को

समझना ही मजदूर आन्दोलन की मुख्य बात है। आपलोग संघर्ष चाहते हैं और संघर्ष के लिये संगठन चाहते हैं और संघर्ष व संगठन से ही खुश हो जाते हैं। लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा। संघर्ष क्यों? संगठन क्यों? निश्चय ही लड़ाई महज लड़ाई के ही लिये तो नहीं हैं। संगठन महज संगठन के लिए ही तो नहीं है। तब फिर लड़ाई, संगठन ये सब आवश्यक है–क्रान्ति के लिए, मजदूरों की मुक्ति के लिये। किससे मुक्ति? शोषण कौन कर रहा है? बाधा कहाँ है? राम मेरा शोषण कर रहा है और मैं श्याम के खिलाफ लड़ने की तैयारी करता रहूँ तो मैं कभी मुक्ति हासिल नहीं कर सकूँगा। इसलिए सही रास्ते का निर्णय कर पाना अत्यधिक महत्वपूर्ण सवाल है। ईमानदारी, निष्ठा, आत्मत्याग, संघर्ष की मानसिकता रहते हुये यदि रास्ता गलत हो तो सारी मेहनत बेकार जाने के सिवा कुछ नहीं होगा। याद रखियेगा ये सब प्राथमिक बुनियादी गुण (Elementary Basic Quality) हैं जिनके न होने से क्रान्तिकारी ही क्यों प्रतिक्रियावादी लोग भी कुछ नहीं कर सकते। फासिस्ट, नात्सी लोग, जिन्होंने जर्मनी में फासिस्ट राजसत्ता की स्थापना की थी, क्रान्ति को रोका था, प्रतिक्रान्ति को जन्म दिया था, जापानी साम्राज्यवाद जिसने तमाम दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों पर अपने जघन्य साम्राज्यवादी शासन व जुल्म को चालू किया था, पिछले महायुद्ध के दरम्यान जो इतने बड़े खतरे के रूप में उभरा था उसके अनुयायी लोग वे सभी जाने या अनजाने नैतिक बल के आधार पर इस आदर्श को ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनाये हुये थे। वे 'हाराकिरी' करते थे। हाराकिरी शब्द आपलोगों ने अवश्य सुना होगा। इस जापानी साम्राज्यवादी उद्देश्य के अनुयायी जब सोचते थे कि जिस फर्ज को उन्हें निभाना था, वे निभा नहीं पाये, फौज के साथ, राष्ट्र के साथ उन्होंने गद्दारी की तब वे अपने आप को सजा देते थे। यह निष्ठा और अनुशासन की निशानी है। नात्सियों की जीवन कथा पढ़ने से, उनके अनुशासन की कहानी पढ़ने से समझ सकेंगे कि यह भी एक प्रकार का अनुशासन है। यह एक प्रकार की संग्रामी मानसिकता (militancy) है। जिसकी आवश्यकता प्रतिक्रियावादियों को भी होती है। जो भी कुछ लोग करना चाहते हैं उन्हें उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन जो इन सब से बड़ी व महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि मूल 'राजनैतिक लाइन' सही है या नहीं? मूल राजनैतिक दृष्टिकोण सही है या नहीं? जिस वस्तु का आप निर्माण करना चाहते हो ईमानदारी होते हुये भी उसके संबंध में यदि आपकी कोई सही विज्ञान संगत धारणा न हो तो आप उसका निर्माण नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप मान लीजिए टिंचर आयोडीन तैयार करने के लिए जिन-जिन चीजों (Ingredients) को मिलाना पड़ता है, आपको उसकी जानकारी नहीं है। आप चुना, बालू और बजरी मिलाकर उसे तैयार करने के लिये कठिन परिश्रम कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, यहाँ तक कि जान भी दे डालने को तैयार हो सकते हैं फिर भी चूँकि आप में निष्ठा और ईमानदारी की कोई कमी नहीं है मात्र इसीलिये इस तरीके से क्या आप टिंचर आयोडीन तैयार कर सकेंगे? निष्ठा, ईमानदारी, एकाग्रता आवश्यक है इसलिये मात्र इन्हीं गुणों को मूलधन मानकर किसी मन-गढ़ंत धारणा से क्या कोई इस मिश्रण को तैयार कर सकेगा? राजनीतिक, सामाजिक क्रिया कलापों में भी यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण और जरूरी है। आप लोगों को यह समझना होगा कि भारत की यह क्रान्ति किस तरह की क्रान्ति है। भारत के इस आर्थिक शोषण का मूल कारण क्या है? इसकी राजसत्ता का चरित्र क्या है? अर्थात् किस वर्ग ने इस पर कब्जा कर रखा है? जब तक इन प्रश्नों के बारे में साफ धारणा नहीं होगी तब तक, क्रान्ति का मूल रास्ता जिसे हम मूल रणनीति व रण-कौशल (Strategy and Tactics) कहते हैं, तय नहीं कर पायेंगे। यहाँ यदि कोई क्रान्ति के उद्देश्य से भी मनगढ़ंत धारणा लेकर गलत सिद्धान्त के आधार पर किसी गलत पार्टी का गठन करे तो लोगों की दु:ख-दुर्दशा के सवालों पर कुछ लड़ाइयाँ लड़ते रहने से शायद कुछ दिनों के लिये लोगों को संगठित कर वह एक ताकतवर पार्टी गठित कर लें, परन्तु क्रान्ति नहीं कर पायेंगे। उल्टे इसके जरिये लोगों में संघर्ष करने की जो आकांक्षा है वह गलत रास्ते संचालित होने के फलस्वरूप क्रान्तिकारी शक्ति को बर्बाद कर देगी, जिसका नतीजा यह होगा कि पूँजीपति व प्रतिक्रियावादी तत्व मौके का फायदा उठाकर अपने को और भी ज्यादा ताकतवर बना लेंगे। इसलिये हमें अच्छी तरह समझना होगा कि भारत की मूल समस्याएँ क्या हैं और क्यों समस्याएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। मेरे विचार से भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन की सभी समस्याओं, सारी उथल-पुथल की जड़ में तीन मूल समस्याएँ हैं। सांस्कृतिक पतन-जिसके बारे में इससे पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ–को भी समझने के लिये इन तीन मूल समस्याओं को अच्छी तरह समझना होगा।

भारत के सामाजिक जीवन की तीन मूल समस्याएँ

हमारे सामाजिक जीवन की सभी समस्याएँ जिन तीन मूल समस्याओं से जुड़ी हुई हैं। उनमें प्रधान है-निरंतर बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या। इस समस्या का हल किसी भी तरह नहीं हो पा रहा है। एक के बाद एक योजनाएं लागू की जा रही हैं और बेकारों की संख्या बढ़ती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वे लोग कहते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या इसका मूल कारण है। यह बात सच है या नहीं, सही मायने में यही कारण है या नहीं, यह तभी विचारणीय विषय माना जा सकता था जब पहले यह साबित कर पाते कि देश में जितने संसाधन (Resources) यानी उत्पादन क्षमता व श्रमशक्ति मौजूद है उसकी बर्बादी नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार नहीं है, फिजूलखर्ची नहीं है, लगी हुई उत्पादिका-शक्ति (Installed capacity) बेकार पड़ी नही रह रही है। उसका पूरा-पूरा इस्तेमाल हो रहा या इस्तेमाल करने की ईमानदारी से कोशिश की जा रही है या नहीं। इसके बाद भी, यानी ये सब करने पर भी यदि बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा सकता, केवल तभी बढ़ती हुई जनसंख्या एक समस्या के तौर पर विचारणीय हो सकती थी। परन्तु यहाँ सब कुछ उल्टा ही हो रहा है।

यहाँ जितनी भी उत्पादिका शक्ति है, उसी का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। भ्रष्टाचार तथा फिजूलखर्ची (Wastefull practice) हर रोज बढ़ती जा रही है, हर सीमा पार कर गई है। तो निष्कर्ष क्या निकला? क्या बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही उत्पादिका शक्ति को पूरी तरह काम में लगाना संभव नहीं हो पा रहा है?

(शेष पृष्ठ 4 पर)

मजदूर आन्दोलन में...

(पृष्ठ 3 का शेष)

क्या इसी वजह से भ्रष्टाचार तथा फिजूलखर्ची बन्द नहीं हो पा रही? फिर यह तो धोखा देने वाली बात है और इसी धोखे को विश्वास करने लायक बनाने के लिये विशेषज्ञों (Technocrats) के पीछे, कमीशनों और कांफ्रेंसों के पीछे, करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है। अब देश टेक्नोक्रैट (Technocrats) रूपी मूर्खों का स्वर्ग बन गया है। हमारे देश में विशेषज्ञ का मायने पंडित नहीं है बल्कि उसका मायने है–विशेष रूप से अज्ञ यानी महामूर्ख! वर्ना वे इस तरह की व्याख्या नहीं दे पाते कि लगातार बढ़ती हुई बेकारों की समस्या का मूल कारण जनसंख्या की वृद्धि है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि बेकारी की समस्या कोई समस्या ही नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वह यह कि बेकारी की समस्या से जुड़े जो प्रश्न हैं उन पर शासक व शोषक वर्ग उल्टी-सीधी नाना प्रकार की बातें बनाकर चतुराई से पर्दा डालना चाहते हैं। वे बढ़ती हुई जनसंख्या की दुहाई देकर ऊधों की टोपी माधों के सर वाली बात कर रहे हैं। वे असली बात से बच के निकल जाने की कोशिश में हैं।

बेकारों को नौकरी क्यों नहीं लग पा रही? सिर्फ नये-नये उद्योगों कल-कारखानों को खोलने के जरिये ही तो बेकारों को रोजगार दिया जा सकता है। जरूरत रहे या न रहे प्रशासन के ऊपरी ढाँचे को (Top heavy administration) को बड़ा बनाकर उसमें आखिर कितने लोगों को नौकरी दी जा सकती है? उसकी एक सीमा होती है और नतीजा बुरा होता है। एक विशालकाय सेनावाहिनी (Inflated Army) और एक विशालकाय पुलिसवाहिनी बैठी-बैठी खा रही है। इसका बुरा नतीजा समाज के जीवन पर पड़ेगा ही। इसके फलस्वरूप सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में, प्रशासनिक क्रिया-कलापों में परजीवीवाद व्यापक रूपों से काम करेगा। लेकिन वह तो दूसरी बात है। चलिए राष्ट्रीय फिजूलखर्ची की बात भी छोड़ दी जाये। फिर भी, भला कितने लोगों को इस तरह काम देना संभव हो सकेगा? आजकल एक और नया रोजगार केन्द्र (Employment avenue) खुला है। वह है सेवा दल या स्वयंसेवक वाहिनी का गठन करना। राजनीतिक पार्टियाँ खुद ही एक-एक व्यावसायिक संस्थान हो गई हैं जहाँ नौकरी की जगहें हैं, नौकरी मिल सकती है। अर्थात् पार्टी की तरफ से लाठी पकड़ने, स्वयंसेवक का काम करने, चुनाव में काम करने के लिए दैनिक पाँच रुपये से दस रुपये तक मिलेंगे। यह भी इस देश में शुरू हो गया है। भारी संख्या में बेरोजगार नौजवानों को इस तरह काम दिया जा रहा है, जिसे दुनिया में और कहीं किसी ने कभी नहीं सुना। और, इस देश के बड़े-बड़े किसान, महाजन, धनीलोग, कालाबाजारिए, जखीरेबाज, सट्टेबाज लोग आर्थिक दुर्दशा से पीड़ित लोगों को भारी संख्या में गन्ना, चावल आदि चोरी से पार करने के काम मे लगा रहे हैं। इस देश मे चोरबाजारी जैसा अनैतिक जीवन-यापन का पथ भी मानो खुली चीज हो गयी है। खुलेआम नकली राशनकार्डों के जरिये राशन गल्ला, चावल, चीनी आदि को दूसरी जगह ज्यादा दाम में बेचा जा रहा है। इस देश की सरकार सब कुछ बैठी देख रही है, उसे शर्म नहीं आती है। सभी इन बातों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसी हालत में कोई नैतिक मान कैसे बचा रह सकता है? खैर, इस तरह के विभिन्न उपायों से लोगों के रोजगार पाने की कोशिश भी क्या रोज-रोज बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या के दबाव को कम कर सकती है? केवल औद्योगिक विकास के पथ को प्रशस्त करने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण और यंत्रीकरण का प्रश्न जुड़ा हुआ है। कृषि व्यवस्था का आधुनिकीकरण न होने से देहातों में बसने वाले पचहत्तर से अस्सी फीसदी लोगों की दु:ख-दुर्दशा को दूर करना सम्भव नहीं है। क्योंकि अगर औद्योगिक विकास की धारा को निर्बाध न रखा जाय तो कृषि अर्थव्यवस्था के आधुनिकरण के फलस्वरूप जो लाखों लाख लोग बेकार होंगे उन्हें नये-नये उद्योगों में काम देना सम्भव नहीं होगा। लेकिन जहाँ पहले से ही शहर के कल-कारखानों में लाल बत्ती जल रही है, शहरों में बेकारों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कारखाने चालू थे वे बन्द हो रहे हैं। वहाँ कृषि का आधुनिकीकरण कैसे होगा? और कृषि का आधुनिकीकरण नहीं होने से देहातों की हालत सुधर नहीं सकती, बाजार में लोगों की खरीद-शक्ति (Purchasing Power) नहीं बढ़ सकती, यानी बाजार का विस्तार (Extension of market) नहीं हो सकता और बाजार का विकास न होने से उत्पादन कैसे बढ़ेगा? यह एक तरह का कुचक्र बना हुआ है। तो इन सब प्रश्नों के साथ कौन-सा सवाल जुड़ा हुआ है?

हमारे देश में उत्पादन के विकास में रुकावट कौन पैदा कर रहा है? यहाँ पूँजी लगाने (Investment of capital) में बाधा क्या है? इसका एक ही जवाब है और वह यह कि बाजार नहीं है। तो, यह बाजार की समस्या किसकी है? पूँजीवाद की या सामंतवाद? या समस्या की जड़ मिश्रित परिघटना (Mixed phenomenon) है? मैं इस तर्क में नहीं जाना चाहता कि यहाँ सामंतवाद कितना है, कितना नहीं है। मेरे पास यह अत्यन्त अप्रासंगिक प्रश्न है। पहला तो यह कि हमारे देश में भूमि-संबंध के क्षेत्र में सामंतवाद नहीं है। यदि अभी समय होता तो मैं युक्ति और तथ्यों के द्वारा विस्तृत चर्चा के जरिये प्रमाणित कर देता। लेकिन यदि बहस की खातिर मान भी लें कि कहीं भूमि-सम्बन्ध के क्षेत्र में अभी भी सामंतवाद मौजूद है, तब मार्क्सवाद कहता है–मिश्रित परिघटना (Mixed phenomenon) के मामले में विचार करने के लिए उस परिघटना की मुख्य या प्रधान विशेषता (Dominant characteristic) का पता लगाना पड़ता है और उसी के आधार पर उक्त घटना के चरित्र का अध्ययन करना पड़ता है। अब देखा जाये, भारत की अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? यह पूँजीवाद है या सामंतवाद? भारत की अर्थव्यवस्था का मूल ढाँचा सामंतवादी है या पूँजीवादी?

कृषि अर्थव्यवस्था समेत भारत की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में इजारेदार पूँजी का नियम लागू है

प्रश्न यह है कि देश में आज इस्पात की पैदावार के सामने यह जो अड़चन आ रही है, इसे कौन लोग पैदा कर रहे हैं? क्या सामंत लोग? या पूँजीवादी बाजार संकट के चलते ही ऐसा हो रहा है? यहाँ कि उत्पादन-क्षमता सुस्त व बेकार पड़ी है, क्या इसकी वजह पूँजीवादी बाजार संकट नहीं है? क्या आज पूँजीवादी उत्पादन-सम्बन्ध प्रभावहीन हो गया है? यदि कोई सांख्यिकी के द्वारा दिखाये भी कि यहाँ कुछ लोगों के हाथों में जमीन है–जिन्हें कोई-कोई पूँजीवादी जमींदार (capitalist landlord) की संज्ञा भी दे रहा है, तो इससे भी यह बात साबित नहीं होती कि ग्रामीण-अर्थव्यवस्था में मूल उत्पादन-सम्बन्धों (dominant production relations) के तौर पर सामंतवाद, अर्द्धसामंतवाद विराजमान है। यह सही है कि कृषि अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद जमींदारी (capitalist landlordism) जैसा शब्द है। यह तो यहाँ तक कि, इंग्लैण्ड में भी है। एक समय अमेरिका में भी कुछ अवधि के लिए कहीं-कहीं यह पनप उठी थी। उन्हें पूँजीवादी जमींदार कहा जाता है। वे तो पूँजीवाद से ही सम्बन्धित हैं। वह तो पूँजीवाद के साथ सामंती ताकतों की मिलावट (Alloy) की तरह मिश्रित हो जाने की बात है। जिसे पूँजीवाद को उखाड़ फेंकने के जरिये ही मिटाया जा सकता है। वहाँ पूँजीवाद को कायम रखते हुये इस सामंती आदत को मिटाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये सब बे-सिर-पैर की बातें करके क्रान्ति के असल सवाल को ही घोलमट्ठा किया जा रहा है।

यहाँ राजसत्ता पूँजीपति वर्ग के हाथों, बुर्जुआ वर्ग के हाथों में है। राजसत्ता को उखाड़ फेंकने की लड़ाई का ही नाम क्रान्ति है। मजदूर जो लड़ेंगे, संगठन बनायेंगे वह तो आखिर तक इस शोषण-मूलक राजसत्ता को ही उखाड़ फेंकने के लिए। इसका मतलब यह है कि राजसत्ता पर आसीन एक वर्ग से सत्ता की ताकत छीन लेंगे। उस वर्ग की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था पर चोट कर उसे ध्वस्त कर देंगे। लेकिन जिस वर्ग को सत्ता से उखाड़ फेंका जायेगा, वह कौन सा वर्ग है? कौन से वर्ग की अर्थ-व्यवस्था पर चोट करेंगे? क्या यह चोट पूँजीवादी अर्थव्यवस्था, पूँजीवादी समाज-व्यवस्था और पूँजीवादी राजसत्ता पर होगी या किसी दूसरे पर? लेकिन इस मूल विषय को ही घोल-मट्ठा करने के कारण कई लोग साम्राज्यवाद व सामंती व्यवस्था के साथ ही साथ इजारेदार पूँजीवाद के खिलाफ भी नारे लगा रहे हैं। इजारेदार पूँजीवाद के खिलाफ तो सभी लोग यहाँ तक कि छात्र परिषद, युवक कांग्रेस भी नारे लगा रही है। सी.पी.आई., सी. पी.आई.(एम.) भी इसी एक ही स्वर में नारे लगा रही है। सभी की एक ही चाल है। इजारेदार पूँजी या किसी एक व्यक्तिगत इजारेदार जैसे टाटा-बिड़ला के खिलाफ लड़ाई क्या पूँजीवाद के खिलाफ, बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ लड़ाई है या व्यक्ति के खिलाफ? इसलिए नारे का वर्ग के खिलाफ होना जरूरी है। इजारेदार पूँजीपति कोई अलग वर्ग नहीं है। वह एक गुट है। धनकुबेरों का गुट (Financial Oligarchy) जो वित्तीय पूँजी के अधिकारी बैकों व उद्योगों के मालिक हैं। जिस पूँजीपति वर्ग पर हम चोट करना चाहते हैं यह गुट उस पूँजीपति वर्ग का नेता है। लेकिन नेता को सामने रखकर वर्ग को निशाना न बनाने का मायने तो हमारे मूल दुश्मन पूँजीवाद को ही सुरक्षित रखना है। तो, क्या बुर्जुआ वर्ग को निशाना बनाये बिना हम बुर्जुआ वर्ग को हटा सकते हैं। देखियेगा मार्क्स, एंगेल्स ने एवं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की दसवीं कांग्रेस में चाऊ-एन-लाई ने भी नाना प्रकार से यह बात कही है कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। व्यक्ति के चले जाने पर भी जब तक वर्ग रहेगा इजारेदार पूँजी (मोनोपॉली) फिर से जन्म लेगी। 'मोनोपॉली' के मायने सिर्फ बिड़ला नहीं है। पूँजीवादी व्यवस्था का, बुर्जुआ वर्ग के शासन का एक अनिवार्य परिणाम 'मोनोपॉली' है इसलिए जब तक पूँजीवाद रहता है तब तक एक बिड़ला के चले जाने से सैंकड़ों बिड़ला पैदा होंगे। इसलिए जब तक लड़ाई टाटा के खिलाफ, बिड़ला के खिलाफ या किसी कारखाना मालिक के खिलाफ लड़ी जाती है यदि उसे पूँजीवाद को उखाड़ फेंकने के नजरिये से संचालित न किया जाये, यदि जनता को, मजदूर वर्ग को बुर्जुआ वर्ग-शासन उखाड़ फेंकने की क्रान्तिकारी चेतना व आदर्श से संगठित न किया जाये तो वह लड़ाई चाहे उसमें कितने ही जोशीले नारे क्यों न हों, दरअसल पूँजीवाद पर कहीं प्रहार नहीं करती, तनिक भी चोट नहीं पहुँचाती।

भारत की क्रान्ति है पूँजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति

इस तरह यह साफ है कि इन सब नकली क्रान्तिकारी पार्टियों के तथाकथित इजारेदार पूँजीवाद-विरोधी नारों का असली मकसद इस देश की पूँजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति को हटाने के लिए पूँजीवाद के सामूहिक हित के रक्षार्थ टाटा या बिड़ला को बलि का बकरा बनाने के अलावा और कुछ नहीं है। इस देश में क्रान्ति को समझने के लिए अत्यन्त आवश्यक तथा सहज बातों को इसी तरह गोलमोल किया जा रहा है। जहाँ सत्ता बुर्जुआ वर्ग के हाथों में है वहाँ बुर्जुआ वर्ग को राजसत्ता से उखाड़ फेंकने की क्रान्ति को ही तो मार्क्सवादी-लेनिनवादी परिभाषा में समाजवादी क्रान्ति कहा जाता है। राजसत्ता पर बुर्जुआ वर्ग के साथ पाँच-दस सामंत रहने से क्रान्ति का स्तर पलट नहीं जाता। रूस की क्रान्ति का इतिहास पढ़ने से देखेंगे, फरवरी (1917 ई0) की जनतान्त्रिक क्रान्ति के बाद जिस करेंस्की की सरकार का गठन हुआ था, उसके मन्त्रिमण्डल में, रक्षा, वित्त, विदेश आदि महत्वपूर्ण दफ्तर सभी तो जार परिवार के सदस्यों के हाथ में थे, इसके बावजूद 'अप्रैल थीसिस' में लेनिन ने कहा है कि "जैसे ही निकोलाई जार को हटाकर राजसत्ता पूँजीपति वर्ग के हाथों में चली गई उसी क्षण रूस की क्रान्ति समाजवादी क्रान्ति के स्तर पर प्रवेश कर गई, राजनैतिक पहलू से बुर्जुआ जनवादी क्रान्ति पूरी हो गई"।

क्या लेनिन नहीं जानते थे कि उस समय में कुलक लोग (धनी भूस्वामी) थे, कुलकवाद मौजूद था? जार का प्रभाव खत्म नहीं हुआ था? साम्राज्यवादियों की पूँजी भारी मात्रा में वहाँ लगी हुई थी और अर्थव्यवस्था में भी साम्राज्यवादियों का प्रभाव पूर्ण रूप से मौजूद था? मार्क्सवादियों का एक तबका वहाँ भी था जो इस सब का जिक्र करते हुये चिल्लाता था कि साम्राज्यवाद व सामंतवाद को पूरी तरह खत्म किये बगैर एक छलांग में समाजवादी क्रान्ति कैसे होगी?

(शेष पृष्ठ 6 पर)

परीक्षा–फल में हुई धांधली व भ्रष्टाचार का विरोध

पटना (बिहार): मैट्रिक और इंटर के परीक्षा-फल में हुई भारी पैमाने पर धांधली व भ्रष्टाचार के विरोध में तथा उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन का अधिकार की मांग पर 21 जून को ऑल इंडिया डीएसओ ने मुख्यमंत्री के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन गांधी मैदान स्थिन भगत सिंह चौक से निकाला गया, लेकिन पुलिस उसे आगे नहीं जाने दे रही थी। फिर भी धक्कामुक्की करते हुए कार्यकर्ता नेताजी सुभाषचन्द्र बोस मूर्ति तक पहुंच गये। मगर यहां से पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। यहीं पर एक सभा आयोजित की गयी।

राज्य के विभिन्न जिलों से आये छात्र हाथों में झंडे-बैनर के साथ अपनी मांगों से संबंधित तख्तियां लिये हुए थे। तख्तियों पर 'मैट्रिक एवं इंटर के परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी करने वाले सभी दोषियों को गिरफ्तार कर दृष्टांतमूलक सजा दो,' 'गिरफ्तार टॉपर माफियाओं पर स्पीडी ट्रायल चलाकर उन्हें सख्त सजा दो', 'परीक्षा केन्द्र पर एवं उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ', 'उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन का अधिकार दो' 'प्राथमिक स्तर से पास-फेल प्रथा लागू करो' आदि मांगें लिखी हुई थी।

छात्रों को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया डीएसओ बिहार राज्याध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कहा कि बिहार में 'पैसा दो शिक्षा लो' यानी शिक्षा के बाजारीकरण के साथ-साथ 'पैसा दो मनचाहा रिजल्ट लो' का धंधा जोरों पर चल रहा है। राज्य में ऐसे सैकड़ों कॉलेज हैं, जहां पैसे पर डिग्री देने का काम चल रहा है। सरकार के नजदीकी रसूख वाले लोगों द्वारा राज्य भर में इस तरह का रैकेट संचालित हो रहा है। लेकिन सरकार अपने राजनीति लाभ के लिए इस पर सख्ती से रोक नहीं लगा रही है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन और परीक्षा-फल प्रकाशन में काफी गड़बड़ी व्याप्त है। प्रश्न-पत्र लीक होना आम बात हो गयी है। विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री बेचने की दुकान बनकर रह गये हैं।

सभा को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया डीएसओ बिहार राज्य सचिव रोशन कुमार रवि ने कहा कि मैट्रिक और इंटर के परीक्षा-फल में हुई भारी धांधली व भ्रष्टाचार से बिहार की जनता भारत में ही नहीं, विदेशों में भी शर्मिन्दा हो रही है। शिक्षा जगत में हर साल उजागर हो रही इस तरह की चौंकाने वाली नयी-नयी वारदातें राज्य की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को प्रदर्शित करती हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का '74 के प्रख्यात छात्र आंदोलन जुड़ाव रहा है। लेकिन आज उन्हीं के शासन में बिहार की शिक्षा बदहाली के आंसू बहा रही है। सरकार की ही जांच रिपोर्ट बताती है कि शिक्षा की गुणवत्ता में काफी कमी आयी है। परीक्षा संचालन और परीक्षा फल में हो रहे घोटाले और गड़बड़ियों के तार सत्ता के गलियारे में जुड़े हुए पाये जा रहे हैं। राज्य में गरीब-निम्न मध्यमवर्गीय अभिभावकों और लाखों बच्चों के सपने तार-तार हो रहे हैं।

सभा को राज्य सचिव मंडल सदस्य सरोज कुमार सुमन, विजय कुमार, पुष्पा, सुमनलता मौर्य; राज्य कमिटी सदस्य शिव कुमार, श्यामदेव कुमार, राजू कुमार तथा निकोलाई शर्मा इत्यादि ने भी संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने राज्य की बदहाल परीक्षा व्यवस्था व उसमें हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों को आगे आकर आंदोलन तेज करने की अपील की ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सके।

हरियाणा में बुढ़ापा पैन्शन पर लगाई गई नाजायज शर्तों के खिलाफ

सड़कों पर उतरे एसयूसीआई(सी) कार्यकर्ता

हरियाणा में बुढ़ापा पैन्शन पर लगाई गई नाजायज शर्तों को तुरन्त वापस लेने की मांग को लेकर 21 जून को एसयूसीआई(सी) की ओर से जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किये गये और जिला उपायुक्तों की मार्फत माननीय मुख्यमन्त्री, हरियाणा सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश सरकार ने तरह-तरह की नाजायज शर्तें लगाकर बुढ़ापा पैन्शन में कांट-छांट करने का जो फैसला किया है वह सामाजिक न्याय का गला घोंटने वाला एक जनविरोधी व अन्यायपूर्ण कदम है। ज्ञापन में मांग की गई कि बुढ़ापा पैन्शन पर लगाई गई तरह-तरह की नाजायज शर्तों के इस काले फरमान को सरकार तुरन्त वापस ले। वक्ताओं ने का कि बुढ़ापा पैन्शन कोई खैरात, भीख या प्रसाद नहीं है जो सरकार किसी को दे या नहीं दे। बुढ़ापा पैन्शन बुजुर्गों का बुनियादी हक है। 60 साल की उम्र होने तक जो अपनी कड़ी मेहनत से खेत, खलिहान, खान-खदान या कल-कारखानों आदि में जहाँ-तहाँ उत्पादन-पैदावार में भागीदारी करते हैं, देश की धन-दौलत बढ़ाते हैं, समाज को भोजन, कपड़ा, मकान देते हैं, मरते दम तक लगे रहते हैं, क्या बुढ़ापे में उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का कोई हक नहीं है?

भिवानी में एसयूसीआई(सी) के जिला सचिव कॉ. रामफल, जिले सिंह, रोहताश, धर्मवीर, उम्मेद सिंह आदि ने अगुआई की। रोहतक में 24 जून को प्रदर्शनकारी जिला सचिव कॉ. अनूप सिंह मातनहेल के नूतृत्व में मानसरोवर पार्क में इकट्ठे होकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए उपायुक्त कार्यालय तक आये और उपायुक्त की मार्फत ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों को कॉ. जिले सिंह, हरीश कुमार, जयकरण और जगदीशचन्द्र ने सम्बोधित किया। सोनीपत में एसयूसीआई(सी) की तरफ से जनसमस्याओं को लेकर अंबेडकर पार्क से उपायुक्त कार्यालय तक जुलूस निकाला गया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सभा को पार्टी के जिला सचिव कॉ. ईश्वर सिंह राठी व कॉ. हरिप्रकाश ने सम्बोधित किया।

मिड डे मील वर्कर्स ने मांगा सरकार कर्मचारी का दर्जा

नारनौल : मांगों के लिए सड़कों पर उतरी मिड-डे मील कार्यकर्ता

नारनौल(हरियाणा) : मिड-डे मील कार्यकर्ता यूनियन (सम्बन्धित एआईयूटीयूसी) की जिला महेन्द्रगढ़ इकाई एवं स्वयं सहायता समूह की कार्यकर्ताओं ने 21 जून को यहां जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और सरकार से सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और न्यूनतम वेतन 18000 रुपये मासिक लागू करने की मांग की।

मिड-डे मील कार्यकर्ता लम्बे अर्से से इन मांगों के लिए संघर्षरत हैं। प्रदेश सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इससे उनमें सरकार के प्रति भारी रोष है। प्रदर्शनकारियों में जिला सचिव बिमला देवी, हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के महासचिव मास्टर सूबे सिंह, डीवाईओ के सतीश, मीना, मंजू, आदि प्रमुख थे।

मजदूर आन्दोलन में...

(पृष्ठ 4 का शेष)

लेनिन ने अच्छी तरह उनके कान ऐंठ कर एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात कही थी कि मार्क्सवाद आर्थिक निश्चयतावाद (Economic determinism) नहीं है। कहा था कि राजनीति को अर्थनीति से प्राथमिकता देनी होगी और इस मुद्दे को दूसरे ढंग से देखने का अर्थ होगा, मार्क्सवाद के क-ख-ग को ही भूल जाना। (Politics must take precedence over economics and to argue otherwise is to forget ABC of Marxism).

राजनीति एवं अर्थनीति के बीच जो आपसी सम्बन्ध हैं, वह ऐसा यांत्रिक नहीं है कि राजनीति केवल अर्थनीति का अनुसरण कर रूप लेती रहती हो। जैसे आर्थिक क्षेत्र में सामंतवाद एवं साम्राज्यवाद का प्रभाव मौजूद रहने के बावजूद राजनैतिक क्षेत्र में पूँजीपतियों के द्वारा राजसत्ता पर कब्जा किये जाने के जरिये एक सवाल सामने आ गया। सिर्फ इसी घटना के आधार पर लेनिन ने कहा था–चूँकि आर्थिक क्षेत्र में इन परिवर्तनों के होने से पहले ही पूँजीपतियों ने राजसत्ता पर कब्जा कर लिया है, इसलिये उन्हें अब बिना हटाये सामंतवाद और साम्राज्यवाद को हटाना कतई सम्भव नहीं है। इस मायने में तथा इस हद तक (In that respect and to that extent) रूस की क्रान्ति समाजवादी क्रान्ति है एवं जब तक इस क्रान्ति को पूरा नहीं किया जाता तब ये दोनों, साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद मिलावट (Alloy) की तरह उसके (पूँजीवाद के) साथ मिले रहेंगे।

लेकिन हमारे देश में कुछ तथाकथित मार्क्सवादी लोग मार्क्स-लेनिन से कोई शिक्षा लिये बिना तथा इस बात की परवाह किये बिना कि यहाँ पूँजीवादी राजसत्ता है, क्रान्ति का स्तर निर्णय करने के मामले में यही मुख्य विचारणीय बात है कह कर शोर मचा रहे हैं कि इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सामंतवाद का अस्तित्व है। उनका तर्क है–अभी देहातों में पुराने जमाने के तरीकों से छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटी हुई जमीन में खेती होती है। चंद लोगों के हाथ में ज्यादातर जमीन है। बड़े पैमाने पर खेती तथा उन्नत किस्म की मशीनों का प्रयोग जैसा कि विकसित पूँजीवादी देशों में देखा जाता है, वह यहाँ मौजूद नहीं है आदि-आदि। इस प्रसंग में लेनिन ने हमें पहले से ही सतर्क करते हुये एक बात कही थी। इस बात पर लेनिन ने बोलते हुए कहा था कि छोटे पैमाने पर टुकड़े-टुकड़े जमीन पर पुराने जमाने की पद्धति से खेती अथवा आधुनिक पद्धति से बड़े पैमाने पर फार्म बनाकर खेती, उन्नत किस्म की मशीनों का इस्तेमाल आदि कुछ भी यह निर्धारित नहीं करता कि कृषि अर्थव्यवस्था का चरित्र सामंतवादी है या पूँजीवादी अथवा समाजवादी। उत्पादन सम्बन्ध और कृषि उत्पादित वस्तुओं के व्यापार-वाणिज्य की रीति किस तरह की है इसी से कृषि अर्थव्यवस्था का सही चरित्र निर्णीत होता है।

अर्थात् कृषि उत्पादित वस्तुओं की खरीद-बिक्री का चरित्र क्या है? उसके व्यापार-वाणिज्य की रीति क्या है? क्या वह स्थानीय कृषि बाजार (Local agricultural market) का बिकाऊ माल है, या वह पूँजीवादी राष्ट्रीय बाजार के व्यापार-वाणिज्य की बिकाऊ वस्तु (commodity circulation) है। अथवा समाजवादी आर्थिक योजना में सामाजिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का सरकार जिस तरह सम मूल्य के आधार पर विनियम करती है, क्या उसी तरह की वस्तु रूप में यह प्रयोग में लाई जा रही है, बाजार के माध्यम से जनता तक पहुँचाई जा रही है और बाजार के माध्यम से मुहैया कराने (Trade and Commerce) की इस व्यवस्था को धीरे-धीरे कम करने के उद्देश्य को सामने रखते हुये कृषि उत्पादन संचालित हो रहा है? किस उद्देश्य से उत्पादन संचालित हो रहा है एवं उत्पादित सामग्रियों का व्यापार-वाणिज्य किस तरह चल रहा है इन बातों के आधार पर ही कृषि अर्थव्यवस्था का चरित्र निर्धारित करना पड़ता है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ जो लोग जमीन के मालिक हैं वे जमीन में पूँजी लगा रहे हैं एवं अतिरिक्त वस्तुओं को बाजार में बेच कर उससे मुनाफा उठा रहे हैं। यहाँ पर उत्पादन मूलत: निजी उपयोग के लिये नहीं हो रहा है। सर्वोच्च दर पर यहाँ मुनाफा कमाना ही उत्पादन का उद्देश्य है। इसके फलस्वरूप जमीन भी कैपिटल या पूँजी में – पूँजीवादी उत्पादन के साधन में रूपांतरित होती जा रही है। कृषि से उत्पादित सामग्री बाजार में बिकने से पूँजी और बढ़ रही है अर्थात् कृषि उत्पादन में मुद्रा-वस्तु-अधिक मुद्रा (M-C-M) नियम पूरी तरह चालू हो गया है। जमीन में पूँजी निवेश के रूप में (Capital Investment) लगाई जा रही है, पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का नियम अत्यन्त सहज एवं साफ है।

इसलिए ये सब बेकार की बाते हैं कि यहाँ टुकड़े-टुकड़े जमीन पर खेती हो रही है या नहीं; मशीन-ट्रैक्टर के द्वारा खेती हो रही है या नहीं। इस देश में क्यों ट्रैक्टर-मशीन तथा उन्नत किस्म के यंत्रों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इस विषय पर मैंने पहले भी कई बार चर्चा की है। जापान में तो छोटी-छोटी जोत की जमीन में खेती होती है। बड़े पैमाने पर फार्म बना कर खेती नहीं होती है तो इससे क्या यह सिद्ध होता है कि जापान पूँजीवादी देश नहीं है? इस देश के पूँजीपतियों ने देखा है कि ट्रैक्टर, मशीन आदि का व्यापक इस्तेमाल करने पर एक ही झटके में लाखों-लाख लोग कृषि से उखड़ कर बेकार हो जायेंगे। अगर कल-कारखानों के निर्बाध विकास का रास्ता खोलकर इन्हें शहरों में काम न दिया जा सका तो फिर पूँजीवाद जो पहले से ही शहरों में लगातार बढ़ते हुये बेकारों के दबाव से हाँफ रहा है, लाखों-लाख नये ग्रामीण बेकारों के अतिरिक्त दबाव से मुँह के बल गिर पड़ेगा।

उन्नीसवीं सदी के पूँजीवाद ने विश्वव्यापी उन्मुक्त बाजार की सुविधा को सामने रख औद्योगिक विकास के हित में ग्रामीण जनसंख्या को उद्योगों में काम में लगाने की मांग से कृषि में ट्रैक्टर-मशीन का इस्तेमाल कर कृषि से अतिरिक्त जनसंख्या को मुक्त किया था। परन्तु आज जबकि विश्वव्यापी पूँजीवादी बाजार का सापेक्ष स्थायित्व समाप्त हो चुका है, वहाँ इस जबरदस्त बाजार संकट से जर्जर, क्रान्ति से भयभीत मरणासन्न पूँजीवाद जिसने कल-कारखानों की मौजूदा उत्पादन क्षमता तक को, उपयोग में लाने में असमर्थ होने के कारण बेकार (Idle) बना रखा है–भला कैसे कृषि का आधुनिकीकरण कर सकता है। कृषि में आमूल सुधार लाने के बजाय उसने उल्टा ही रास्ता अपनाया है। उन्होंने ज्यादातर लोगों को अधभूखी, अधनंगी हालत में छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटी जमीन में फँसा रखा है। और हरित क्रान्ति जैसी धोखेबाजी से लोगों को भुलावा दे रहा है। यह दरअसल संकटग्रस्त बुर्जुआ वर्ग (पूँजीपति वर्ग) की शैतानी भरी योजना है। लेकिन हैरानी तो इस बात पर है कि सी.पी.आई.(एम) जो कृषि भूमिसुधारों की बातें करती हैं, सामंतवाद को उखाड़ फेंकने की बात करती हैं उनकी भी कृषि योजना मुलत: यही है। कृषि में आधुनिकीकरण के लिए मशीन-ट्रैक्टर चालू करने के संदर्भ में उनकी स्वविरोधी बातों पर गौर कीजिये। सी.पी.आई.(एम) ने अपने मुजफ्फरपूर दस्तावेज में कहा कि ट्रैक्टर चालू करने पर वह विरोध करेगी। आन्दोलन छेड़ेगी। क्यों? क्या नीति के तौर पर किसान, मजदूर ट्रैक्टर-मशीन चालू करने के खिलाफ हैं? क्या ट्रैक्टर-मशीन उनके दुश्मन हैं? हाँ पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के रहते मशीन-ट्रैक्टर आने से बेकार बढ़ेंगे, काफी लोग रोजगार खो बैठेंगे–इसलिए कि यहाँ उत्पादन का उद्देश्य है अधिक से अधिक मुनाफा करना। लेकिन समाजवादी समाज व्यवस्था में तो मशीन-ट्रैक्टर बेकारों को जन्म नहीं देते वरन् इसमें ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर उन्नत होता है, आधुनिक बनता है।

इसलिए नारा होना चाहिये–"देहातों की तरक्की के लिए मशीन-ट्रैक्टर आने दो–यह हम चाहते हैं। लेकिन चूँकि पूँजीवादी व्यवस्था में हमारे लिए विकल्प काम की व्यवस्था नहीं की जा रही इसलिए विकल्प काम न देने पर ट्रैक्टर-मशीन चालू नहीं करने देंगे।" अत: खेत मजदूरों, गरीब किसानों को समझना होगा कि जल्द पूँजीवाद को उखाड़ फेंकने की हालत पैदा न कर पाने से ट्रैक्टर-मशीन चालू करने के जरिये देश के लोगों की क्रय-क्षमता न बढ़ाने से, रहन-सहन के स्तर को न उठाने से, बिजली रोशनी न आने से गाँवों का चेहरा बदला नहीं जा सकता। गाँवों की पिछड़ी हुई मौजूदा हालत को सुधारा नहीं जा सकेगा। ग्रामीण जीवन में तरक्की नहीं हो सकेगी। और यह सब तथाकथित कम्युनिस्ट ट्रैक्टर-मशीन चालू करने के खिलाफ आंदोलन को टिकाये रखकर ट्रैक्टर-मशीन चालू करने से लाजमी तौर पर जिस भारी तादाद में बेकारों की फौज तैयार होगी उसे बेरोजगारी-विरोधी आन्दोलन में परिणत करने की बजाय सामंतवाद-विरोधी आंदोलन के साथ जोड़ रहे हैं। इसके साथ भला सामंतवाद का क्या संबन्ध है? सभी तो पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध से जुड़े हुए हैं। वरना हम लोग तो जानते हैं कि पूँजीवाद के विकास के युग में जब पश्चिम के देशों में कृषि अर्थव्यवस्था में कुछ मशीन-ट्रैक्टर चालू किये गये उसमें सामंतवादी अर्थव्यवस्था को उखाड़ फेंकने में मदद ही मिली है। इसलिए मशीन-ट्रैक्टर चालू करने के खिलाफ आंदोलन को सामंतवाद-विरोधी आंदोलन के साथ जोड़ने का सवाल ही कहाँ है? फिर भी इन लोगों के द्वारा किस गजब तरह के तर्क दिये जा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी की भूमिसुधार की नीति या प्रोग्राम के साथ इन सब तथाकथित कम्युनिस्ट व विपक्षी पार्टियों के प्रोग्राम या नीति में कोई फर्क नहीं है। सी.पी.आई. या सी.पी.आई.(एम) आदि पार्टियों के जमीन के बँटवारे के जरिये सामंतवाद-विरोधी क्रान्ति व औद्योगिक क्रान्ति का कार्यक्रम वैसी ही बात है। सीलिंग या हदबन्दी से फालतू जो जमीन है उसे कांग्रेस की घोषणा के अनुसार भूमिहीनों को बाँटना है। यहाँ तक कि हदबंदी को घटाकर पाँच एकड़ तक करने की बात कांग्रेसी मंत्री ने उस दिन भी कही है। तब तो फिर कहना होगा कि वे सबसे बड़े क्रान्तिकारी हैं। क्योंकि इसके जरिये तो और भी उचित तरीके से जमीन का बँटवारा किया जा सकेगा। पर ये सभी कोरी कल्पनायें हैं। क्योंकि अगर हदबंदी से ऊपर जितनी जमीन है इस सब को भी पूरे देश के भूमिहीनों में बाँटा जाये तो एक किसान को ज्यादा से ज्यादा एक एकड़ जमीन मिल सकती है। यह जमीन उसके भी परिवार के भरण-पोषण के लिए न के बराबर है, अलाभकर जोत है। इसके अलावा हल बैल पर खर्चे के अभाव में वह उस जमीन पर खेती नहीं कर सकेगा। फलस्वरूप उत्पादन पर उसकी एक नुकसानदेह प्रतिक्रिया होगी। खाद्य समस्या और भी विकट हो जायेगी। अभाव के कारण यह एक एकड़ जमीन आखिर तक उसके हाथ से निकल जायेगी। अतएव इन प्रोग्रामों में कोई कारगर समाधान की बात नहीं है। यह स्टेट की नीति भले ही हो सकती है।

जमीन का बँटवारा करना एक बहुत बड़ी समस्या है। यह सही है कि अतिरिक्त जमीन को आंदोलन के दबाव से भूमिहीनों में बाँटना जनवादी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन इसके जरिये ही बेकारी की समस्या का समाधान होगा, निर्बाध औद्योगिक विकास का रास्ता खुलेगा, बाजार का विकास होगा–इन सब धारणाओं को केवल वे लोग ही पालते हैं, जनता के बीच इस तरह की गलतफहमियाँ सिर्फ वे ही फैलाते हैं, जो जानबूझकर या अनजाने में, उस पूँजीवाद को ही टिकाये रखने में मदद कर रहे हैं, जो पूँजीवाद आज जन-जीवन की हर समस्या और तमाम तरह की दुर्गति के लिए जिम्मेवार है।

देखिये कैसा अजीबोगरीब है इनका स्व-विरोध। वे ही कहते हैं कि गाँवों में खेतमजदूरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जमीन में पूँजी निवेश हो रहा है। पुराने आर्थिक सम्बन्ध टूटते जा रहे हैं। कह रहे हैं पूँजीवाद कृषि में निर्णायक रूप से प्रवेश का चुका है (Capitalism has made a decisive inroad into agriculture)। यदि कृषि में पूँजीवाद जबर्दस्त रूप से पनपा ही है, तो सामंतवाद भला गावों में क्रान्ति का मुख्य दुश्मन कैसे रह सकता है? तब नये सिरे से फिर व्याख्या होती है–नहीं, नहीं सामंतवाद एक पुराना आर्थिक सम्बन्ध है, वह तो टूट ही रहा है। लेकिन टूटने से क्या होगा! अब सामंती प्रभु लोग धनी किसानों के साथ मिल कर शोषण कर रहे हैं। उनकी व्याख्या के अनुसार सदि सौ-सौ बीघे जमीन का मालिक बन कर कोई गाँव में रहकर खेती करवाये तो वह जमींदार नहीं है। वह होगा धनी किसान और तब वह जनवादी क्रान्ति की मित्र शक्ति है। फिर जमींदार

(शेष पृष्ठ 7 पर)

मजदूर आन्दोलन में...

(पृष्ठ 6 का शेष)

कौन है? जिसकी जमीन की मात्रा चाहे कितनी ही क्यों न हो, यदि वह गाँव में रहकर भी खेती-बाड़ी में भाग नहीं लेगा तो वह जमींदार है। मान लीजिए, एक शहरी व्यक्ति के पास गाँव में पंद्रह बीघे जमीन है, पर वह खेती-बाड़ी नहीं करता तो वह जमींदार है और इस आदमी से कई गुना ज्यादा जमीन का मालिक एक दूसरा व्यक्ति है जो गाँव में रहकर खेती-बाड़ी करता है, इसलिए वह दूसरा आदमी फौरन उनकी जनवादी क्रान्ति का मित्र हो जाता है। इसका कारण यह है कि गाँव में इन लोगों के न रहने से उनका किसान संगठन नहीं बन पायेगा और यदि ये लोग साथ न रहें तो चुनाव में वोट कौन दिलायेगा? ये सब धनी किसान जो गाँवों में रहकर खेती-बाड़ी करते हैं, जमाखोरी करते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, यही लोग गाँव में वोट की राजनीति को नियंत्रित करते हैं। अतएव जो लोग जनवादी क्रान्ति का नारा दे रहे हैं उनकी राजनीति का यही है असली चेहरा। क्या यह कोई क्रान्ति का सिद्धान्त है अथवा यह वर्तमान ढाँचे के ही अन्दर मात्र सुधार का कार्यक्रम है?

क्रान्ति के लिए आवश्यक तीन शर्तें – सही क्रान्तिकारी सिद्धान्त, सही राजनैतिक लाइन और सही क्रान्तिकारी पार्टी

इसलिए मैं आपको लेनिन की उस बात की फिर याद दिला दूँ कि क्रान्तिकारी सिद्धान्त एवं रास्ता ठीक होना जरूरी है। साथ ही साथ क्रान्तिकारी पार्टी का होना आश्वयक है। आप लोग इन तीन शर्तों को पूरा नहीं कर सके तो फिर जिस तरह आप लोगों ने अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसी तरह फिर लड़ेंगे लेकिन लड़ाई-लड़ाई खेल भर ही होता रहेगा। इसलिए ट्रेड यूनियन आंदोलन में शामिल होते हुए आप लोगों को इन सब प्रश्नों पर सोचना पड़ेगा। एकजुट होकर लड़ते-लड़ते सोचिये। लड़ते हुए समझने की कोशिश कीजिये कि दूसरी ट्रेड यूनियनों के साथ कहाँ और क्यों मतभेद हैं? आप लोगों की ओर से इसके लिए तहेदिल से कोशिश होनी चाहिये कि राजनैतिक मतभेद के बावजूद एक ही ट्रेड यूनियन गठित करें। इसके लिए राजनैतिक, सैद्धान्तिक क्षेत्र में, तर्क-वितर्क के क्षेत्र में, एक-दूसरे के बीच सहनशीलता की आवश्यकता है यदि कोई अपने सैद्धान्तिक विचार दूसरों को समझाकर आदर्श के बल पर बहुमत हासिल करते हुए नेतृत्व में आये तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन यदि कोई विचार व्यक्त करने की दूसरे की स्वतंत्रता को खत्म कर, आलोचना के अधिकार को छीनकर, केवल कमिटी के बहुमत के जरिये ही नेतृत्व करना चाहता है तो फिर गुटबाजी या छोटे-छोटे गुटों के गठन का मनोभाव तो आयेगा ही और इस गुटबाजी का अर्थ खामखाह हम सब लोगों के समय की बर्बादी है। एक दूसरे के बिलकुल विरुद्ध चलते हुए परस्पर के विरुद्ध काम करते हुए हम लोग मजदूरों के बीच सही क्रान्तिकारी चेतना व संगठन के निर्माण में जी-जान से नहीं जुट सकते। इसीलिए मजदूरों की एक ही यूनियन गठित करने में धीरज और सैद्धान्तिक सहनशीलता का मुख्य अभाव है। दूसरों के विचार को नहीं सुनूँगा, चर्चा नहीं करने दूँगा, गला दबा दूँगा, इनसे तो टूटन पैदा होगी ही। क्योंकि विचार कभी भी पैरों तले दबा नहीं रह सकता। जैसे आपको अपने विचार में विश्वास है, वैसे ही दूसरे भी अपने विचार में विश्वास रखते हैं। चाहे वह गलत ही क्यों न हो। दो मतों के बीच खुले संघर्ष का अवसर रहना जरूरी है। आप मेरे ऊपर अपने विचार थोपना चाहते हो, तो मैं उसे नहीं मान सकता। इसलिए स्वतंत्र रूप से विचारों का आदान-प्रदान होने से, खुली चर्चा-बहस होने से जनसाधारण को समझने का मौका मिलता है कि कौन ठीक है और कौन गलत। यदि आप ठीक हैं तो फिर तो आपको डरने का कोई कारण नहीं है, बल्कि चर्चा में आपकी जीत निश्चित है। जो गलग जगह पर है, मिथ्या को जकड़े हुए है, जिसमें कमजोरी है केवल वही आपसी चर्चा, तर्क-वितर्क, आलोचना-समालोचना और वैचारिक-संघर्ष से डरते हैं केवल वही एकता के नाम पर, अनुशासन की दुहाई देकर नाना बहानेबाजियों के जरिए कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को इस खुली चर्चा से बाहर रखते हैं। जनसाधारण को गुमराह करते हैं। आप लोग इस रास्ते का परित्याग कीजिए। विचारों का आदान-प्रदान जारी रखिए। इस रास्ते से ही मजदूर वर्ग को एकताबद्ध संग्राम में शामिल करने की कोशिश कीजिए।

संग्राम, आन्दोलन तो करना ही है। ऐसी बात नहीं है कि आप लोग लड़ेंगे नहीं। पेट बड़ी बला है। यदि आज सोचें भी कि लड़ाई से कुछ नहीं होगा, फिर भी दो दिन बाद आपको लड़ाई में उतरना ही पड़ेगा। अभी से उसका आभास मिल रहा है। हजारों-हजार लोग मैदान में उतरेंगे, लड़ाई लड़ेंगे लेकिन हालात को बदलने के लिए उन्हीं तीन चीजों की आवश्यकता होती है, सही मूल राजनैतिक लाइन तथा नजरिया, सही क्रान्तिकारी सिद्धान्त एवं सही क्रान्तिकारी पार्टी। यदि ये न रहें, यदि रास्ता गलत हो तो फिर ईमानदारी, कुर्बानी, संग्राम–किसी के जरिये भी आप लोग आगे नहीं बढ़ पायेंगे। इसलिए मैं लेनिन का यह कथन दुहरा कर पुनः आपको याद दिला दूँ- आप लोग चाहे कितने भी जनवादी आन्दोलन क्यों न करें, मांगों को लेकर कितना ही क्यों न लड़े, शहीद-दिवस मनाएँ, कलेजे का लहू उड़ेल दें, हड़तालों और आंदोलनों में पुलिस से कितना ही मुकाबला करें, आप लोग जैसे गुलाम थे वैसे ही गुलाम रह जायेंगे, पूँजीवाद जस का तस रह जायेगा, शोषण कायम रह जायेगा। तनख्वाह शायद दस-बीस रुपये बढ़ेगी लेकिन बाजार में सामान तो यों ही महंगे हैं और भी कई गुना ज्यादा महंगे हो जायेंगे। फिर तनख्वाह के लिए लड़ेंगे, खून बहायेंगे, पाँच रुपये बढ़ भी जायेंगे, फिर चीजों के दाम बढ़ेंगे। केवल यही नहीं, यह अनिश्चितता, नैतिक जीवन में गिरावट ला देगी। जिस सुख का सपना लेकर परिवार को बसाया है, उस परिवार के भीतर एकांत, अत्यन्त निकट सम्बन्ध के लोगों के बीच समाज में मौजूद सामाजिक बीमारियों की छाप पड़ेगी। आपने सुख की आशा लेकर, अनेकों सपने सजाकर घर बसाया था। घर जाकर देखिएगा जो घर बसाने जा रहे हैं, वहाँ भी शान्ति नहीं है। प्यार नहीं है। इस समाज में किसी भी चीज पर भरोसा नहीं है। यहाँ तक की प्यार का भी कोई मूल्य नहीं है। जिन औलादों के पालन-पोषण के लिए आपने खुद कितने ही कष्ट झेले होंगे, किसी भी चीज की परवाह नहीं की होगी, हो सकता है, देखेंगे उनमें से एक-एक मूर्ति नमूने की है। कोई सिनेमा अभिनेता का 'फैन' है तो कोई किसी खिलाड़ी का 'फैन' है। यानी संक्षेप में यह कहें कि आप अपने निकट संबंधियों के साथ मिलकर अपने को हर चीज से अलग रखते हुए, किसी चीज में न उलझकर, झूठे झमेलों में न पड़कर, राजनीति से दूर रहकर सिर्फ नौकरी-चाकरी और खाने-पीने, सोने में दिन बिताते हुए भी अपने आपको इससे बचा नहीं सकते। सामाजिक समस्या का भूत आपके घर पहुँचेगा ही। आपके व्यक्तिगत जीवन को विषाक्त कर देगा। प्यार को खत्म कर देगा। आपके स्नेह-ममता तक को बर्बाद कर डालेगा। बचने के लिए आप लोगों को लड़ना ही पड़ेगा और इस लड़ाई को क्रान्ति की राह पर ही लड़ना होगा। क्रान्ति की राह मायने क्रान्ति क्रान्ति चिल्लाना नहीं है। यदि आप लोग मजदूरों को क्रान्ति के सही स्तर-निर्णय, राष्ट्र के वर्ग चरित्र के बारे में स्पष्ट धारणा के आधार पर सही क्रान्तिकारी पार्टी के नेतृत्व में संगठित कर सके, यदि उन्हें ठीक-ठीक राजनैतिक शिक्षा से शिक्षित कर पाये, तभी और सिर्फ तभी आप लोग जनता की राजनैतिक शक्ति को जन्म दे पायेंगे, राजनैतिक क्षमता को जन्म देने में कामयाब होंगे और राजनैतिक-सत्ता के अधिकारी होंगे। तभी आयेगा वह सुहाना अवसर जब भारत के करोड़ों शोषित-पीड़ित लोग क्रान्ति का मुँह देखेंगे। उससे पहले तक केवल विक्षोभ और पराजय ही होगी, केवल विस्फोट और हार। इनसे मुक्ति और समाज की मुक्ति या इन्सान की मुक्ति का रास्ता एक ही है – वह है क्रान्ति का रास्ता। इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। इन्कलाब जिन्दाबाद!

(समाप्त)

बेरोजगारी, नशाखोरी, अपसंस्कृति के खिलाफ व अनधिकृत कॉलोनियों में सुधार की मांग को लेकर दिल्ली सचिवालय पर धरना

दिल्ली : ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीवाईओ) की दिल्ली कमेटी के बैनर तले 22 जून को नये रोजगार देने, नशामुक्त दिल्ली, नये स्कूल कॉलेज व अस्पताल खोलने के दिल्ली सरकार के अधूरे वादों को पूरा करने की मांग को लेकर दिल्ली के युवाओं ने दिल्ली सचिवालय के समक्ष धरना दिया। धरने में बैठे युवा अपने हाथों में नारे लिखी पट्टिकाएं लिए हुए थे। उन्होंने 'नशामुक्त दिल्ली का वादा पूरा करो', 'नये रोजगार देने का वादा पूरा करो', रोजगार न मिलने तक बेरोजगारी भत्ता दो', 'ठेकेदारी प्रथा खत्म करो' आदि नारे लगाते हुए दिल्ली सरकार पर अपना रोष प्रकट किया। धरने को विभिन्न इलाकों से आए युवाओं ने शिरकत की। संगठन के दिल्ली राज्य अध्यक्ष राकेश कुमार, कार्यालय सचिव प्रभाष, अमरजीत, नवीन, महेन्द्र, रीतु अस्वाल के अलावा संगठन की राज्य सचिव प्रकाश देवी तथा कॉ. हरीश त्यागी(सदस्य, एसयूसीआई(सी) दिल्ली) ने धरने को सम्बोधित किया।

वक्ताओं ने कहा कि चुनाव के समय आप आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता व युवाओं से रोजगार देने, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने, नये स्कूल-कॉलेज खोलने, दिल्ली को नशामुक्त बनाने के जो वादे किये थे वे सब खोखले साबित हुए। ये सरकार भी कांग्रेस और बीजेपी की तरह ही जनविरोधी सरकार है। 'आप' सरकार बनने के बाद जनता की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ बल्कि हालात और बिगड़ रहे हैं। अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि अपने किए हुए वादों को पूरा करें। वक्ताओं ने दिल्ली की जनता, विशेषकर युवाओं का आह्वान किया कि अपनी बिगड़े हालातों मे बदलाव के लिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। एआईडीवाईओ ही एकमात्र युवा संगठन है जो सरकारों की जनविरोधी-युवाविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। अतः अपने हक की लड़ाई में आगे आएं और आंदोलन को मजबूत करें। सभा का संचालन अमरजीत ने किया।

धरने के बाद ज्ञापन मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at New Delhi PSO on 7-8 and 22-23 Fortnightly , Date of Publication :20 June, 2016

हरियाणा में बिजली कर्मियों की हड़ताल पर लगाये गये एस्मा का विरोध

रोहतक (हरियाणा) : राज्य में 29-30 जून को होने जा रही बिजली कर्मियों की दो दिवसीय हड़ताल पर हरियाणा सरकार द्वारा लगाये गये एस्मा का विरोध करते हुए ऑल इण्डिया यूनाइटिड ट्रेड यूनियन सेण्टर (एआईयूटीयूसी), हरियाणा राज्य अध्यक्ष कॉमरेड सत्यवान ने 25 जून को जारी एक बयान में कहा कि सरकार का यह कदम श्रमिक-कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन अधिकारों और हड़ताल के जनवादी अधिकार पर कुठाराघात है। उन्होंने कहा कि बिजली कर्मचारियों के लगातार विरोध के बावजूद सरकार हरियाणा बिजली निगम की 23 सब डिविजनों को प्राइवेट हाथों में सौंपने पर उतारू है जो न तो बिजली उपभोक्ताओं के हित में है और न ही बिजली कर्मचारियों के हित में। इससे बिजली के व्यापारीकरण का बढ़ावा मिलेगा जो बिजली उपभोक्ताओं के हित में नहीं होगा और बिजली कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा नहीं रहेगी। अगर सरकार ने निजीकरण की इस विनाशकारी नीति को नहीं बदला तो प्रदेश भर में आन्दोलन गठित किया जायेगा। कर्मचारियों की हड़ताल पर एस्मा जैसे काले कानून का इस्तेमाल किये जाने का हम कड़ा विरोध करते हैं और सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि सरकार एस्मा लगाने का निर्णय तुरंत वापस ले, दमन का रास्ता छोड़ कर बिजली कर्मचारियों से बातचीत के रास्ते समस्या का समाधान निकाले, बिजली वितरण आदि सरकारी सेवाओं के निजीकरण की नीति छोड़े और बिजली बोर्ड को दोबारा बहाल किया जाए। हम बिजली कर्मचारियों की 29-30 जून की हड़ताल का पूरा समर्थन करते हैं और लोकतंत्र पसंद आम लोगों का आह्वान करते हैं कि वे बिजली कर्मचारियों की जायज मांगों के समर्थन में आगे आयें और सरकार के इस तानाशाही पूर्ण फरमान का डटकर विरोध करें।

मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की रक्षा की मांग पर कन्वेन्शन

लोगों के लोकतांत्रिक व संवैधानिक अधिकारों पर हमलों के खिलाफ एसयूसीआई(सी), सीपीआई, सीपीआई(एम), सीपीआई-एमएल की पहल पर मध्य प्रदेश के गुना में 12 जून को एक कन्वेन्शन आयोजित किया गया। सभा को एसयूसीआई(सी) के राज्य सचिव कॉ. प्रताप सामल, सीपीआई के कॉ. अमानत अली, सीपीआई(एम) के राज्य सचिव कॉ. बादल सरोज ने सम्बोधित किया। कन्वेन्शन का संचालन कॉ. लोकेश शर्मा ने किया।
(ऊपर) मंच पर उपस्थित नेतागण और (नीचे) सभा का एकांश

पारुल यूनिवर्सिटी काण्ड के खिलाफ महिलाओं ने जताया रोष

अहमदाबाद (गुजरात) : 22 जून को ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) ने यहां पारुल यूनिवर्सिटी काण्ड के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। अहमदाबाद वीमेन्स एक्शन ग्रुप (एडब्ल्यूएजी), मानसी महिला सखी सेवा मण्डल, मजूर महाजन संघ (महिला विंग), गुजरात लोकसमिति की सदस्या और अन्य कई नागरिक भी प्रदर्शन में शामिल हुए।

21 जून को वडादरा में भी प्रदर्शन किया गया और कलैक्टर, वडोदरा जिला व डीआईजी वडोदरा को ज्ञापन सौंपे गये। एक तथ्य पता लगाने वाली टीम ने 22 जून को वाघोडिया का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री, गुजरात सरकार को भी एक खुला पत्र लिखा गया। इसमें महिलाओं पर बढ़ते अपराध की रोकथाम करने की मांग की गई।

उ.प्र. के युवाओं का लगाया दो दिवसीय कैम्प

बदलापुर, जौनपुर (उ.प्र.) : सल्तनत बहादुर डिग्री कॉलेज बदलापुर, जौनपुर में ऑल इण्डिया डीवाईओ उ. प्र. राज्य कमेटी के तत्वावधान में 11-12 जून को दो दिवसीय युवा कैम्प लगाया गया। जनसभा की शुरूआत में सब्जी मण्डी से एक जुलूस भी निकाला गया। कैम्प का उद्घाटन एसयूसीआई(सी) के राज्य सचिव कॉ. बी. एन. सिंह ने किया। एआईडीवाईओ के प्रदेश अध्यक्ष कॉ. हरकिशोर सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। संचालन कॉ. प्रमोद कुमार शुक्ला ने किया।

सभा को सम्बोधित करते हुए एआईडीवाईओ के सर्वभारतीय उपाध्यक्ष कॉ. दीपक कुमार ने कहा कि एआईडीवाईओ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित यह युवा कैम्प एक ऐसे समय पर हो रहा जब पूंजीवादी वैश्विक मंदी के दौर में पूरी दुनिया में बेरोजगारी चरम पर है। खेल-कूद, शिक्षा, कला, साहित्य, संस्कृति सब कुछ को मुनाफा कमाने की वस्तु में तब्दील कर दिया गया है। सभी बेरोजगारों को नौकरी देना तो दूर रहा, जीने लायक बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दिया जा रहा है। उल्टे सरकार 'स्किल इण्डिया' और 'मेक इन इण्डिया' जैसी योजनाएं शुरू करके रोजगार न मिलने के पीछे युवाओं के अयोग्य होने का जोर-शोर से प्रचार करने पर तुली हुई है। अत: सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार युवा आन्दोलन ही युवाओं की समस्याओं के समाधान का एकमात्र रास्ता है। कार्यक्रम को संगठन के प्रदेश सचिव कॉ. रविशंकर मौर्य, राज्य कमेटी सदस्य कॉ. मकरध्वज चौहान, जयप्रकाश मौर्य, यशवंत राव, कमलेश मौर्य, संजय राय, इन्दू शुक्ला आदि ने भी सम्बोधित किया।

कार्यक्रम में सैकड़ों नौजवानों ने भाग लिया। रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। प्रतिनिधि सम्मेलन भी हुआ। कैम्प में खेल-कूद, व्यायाम, ताइक्वांडो, योग के अलावा प्राकृतिक चिकित्सा पर एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। बेरोजगारी, अपसंस्कृति, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता आदि समस्याओं पर चर्चा हुई। वर्तमान में नौजवानों की भूमिका पर कॉ. दीपक कुमार ने युवाओं के सवालों के जवाब दिये। अंत में कॉ. हरकिशोर सिंह का अध्यक्षीय भाषण हुआ। सर्वहारा के महान नेता कॉ. शिवदास घोष पर रचित गान के साथ कैम्प का समापन हुआ।

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C).
Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com फोन नं. : 011-25726631, 9868350503